

पत्रांक-6/अ-7-⁴⁹2002-30.68

झारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

॥ माध्यमिक शिक्षा ॥ झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक -

विषय:-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित किड्स गार्डन, झरिया, धनबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अस्थायी रूप से अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

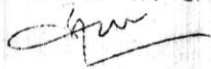
1. विद्यालय की वर्तमान में लीज पर प्राप्त भूमि को विद्यालय प्रबंधन उनके द्वारा दिये गये वापस पत्र के अनुसार छः माह के अन्दर क्रय कर लेगी ।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेशा संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2१६० एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4१६० एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से विनियमित या कम से कम 30१६० वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार



30/030

को सुरक्षित होगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डीमेकान या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट संरक्षण नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, बैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की सशुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं निपुणता प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संगोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित ग्रासी निकाय के सदस्यों की कार्यविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्स्टेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एन0एन0 स्टाउट एवं गार्ड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाणा-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाणा-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

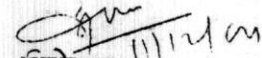
14. अनापति प्रमाणा पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वार्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाणा-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा ~~प्रकरण~~ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

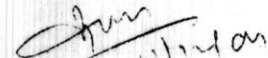
17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायें उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन


निदेशक,

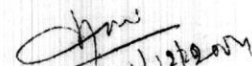
§ माध्यमिक शिक्षा § झारखंड, राँची

ज्ञापक 3000 / राँची, दिनांक - 11.12.04
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित ।


निदेशक,

§ माध्यमिक शिक्षा § झारखंड, राँची

ज्ञापक 3000 / राँची, दिनांक - 11.12.04
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित ।


निदेशक,

§ माध्यमिक शिक्षा § झारखंड, राँची
10/12/04